सिविल सर्विसेज मिनर्वा

सामान्य अध्ययन

वर्ष 9, अंक 6, जून, 2014

मूल्य : 50 रुपये

अनुक्रमणिका

राष्ट्रीय समसामयिकी

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पेश किया मोदी सरकार का एजेंडा 4
मिस्र में सैन्य प्रमुख अब्दुल फताह अल सिसी ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली 4
हर घर में बिजली 5
रिलायंस ही इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट 5

अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी

मोदी की विदेश यात्राओं पर नजर 7
पहली विदेश यात्रा 7
अमेरिका का सवाल 7
तिब्बत के लिए दूसरी मुहिम 7
दलाई लामा का करिश्मा 7
असद की बड़ी जीत 8
जी7 शिखर सम्मलेन 8
ओबामा की सख्ती 8
पुतिन पर निर्भरता 8

भारत और विश्व

भारत–श्रीलंका में मछुआरों का मुद्दा 10
शपथ ग्रहण में आए राजपक्षे 10
भारतीय मछुआरों की दिक्कतें 10
भारतीय मछुआरों का आरोप 10
कहां है विवादित द्वीप कच्चाथीवी 10
भारत–चीन संबंध 10
आर्थिक सहयोग 10
क्षेत्रीय सुरक्षा और संप्रभुता 11
भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बांग्लादेश यात्रा 11

अर्थव्यवस्था/वाणिज्य

मोर पावर टू इंडियाः द चैलेंज ऑफ डिस्ट्रिब्यूशन रिपोर्ट 12
मुख्य तथ्य 12
ऊर्जा क्षेत्र में घाटे के लिए जिम्मेदार कारक 12
सिफारिशें 12
विश्व निवेश रिपोर्ट 2014 12
भारत और विश्व निवेश रिपोर्ट 2014 12

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी)–सी23 के सफल प्रक्षेपण 13
सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र 13
पी.एस.एल.वी. 13
मंगल यात्रा के लिए उड़ी नासा की उड़नतश्तरी 13

पर्यावरण/पारिस्थितिकी

द इंवायरमेंट क्राइम क्राइसिस रिपोर्ट 15
वनस्पतियों और जीवों का अवैध व्यापारः 15
लकड़ी का अवैध व्यापार 15
सिफारिशें 15

पुरस्कार/सम्मान

49वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 16
लीजन ऑफ ऑनर 16

पुस्तकें

एडवर्ड क्लेन द्वारा लिखित पुस्तक ब्लड फ्यूड 17
पदत्याग/पदमुक्त 18
पदत्याग/पदमुक्त 18
सैम पित्रोदा 18

निर्वाचित/नियुक्त

चंद्रबाबू नायडू 19
ज्यां क्लाड जंकर 19

निधन/मृत्यु

एरियल शेरॉन 20
सुचित्रा सेन 20

खेल/खिलाड़ी

35वें राष्ट्रीय खेलों के तिथियों की घोषणा 21
शुभंकर 21
आईबीएसएफ 6–रेड वर्ल्ड स्नूकर खिताब 21

आलेख

4 जी सर्विस 22
रिलायंस जिओ 22
वीडियोकॉन टेलीकॉम 22
वोडाफोन 22
भारती एयरटेल 22
कैसे और क्या होती है ई–वोटिंग 22
कौन कर सकता है ई–वोटिंग? 22
रजिस्ट्रेशन और वोटिंग 22
टाइम पीरियड 22
क्या है अर्निंग यील्ड? 23
शेयर की यील्ड कैसे पता की जाती है? 23
यह इंपॉर्टेंट क्यों है? 23
करेंट एकाउंट डेफिसिट की फंडिंग 23
सीएडी की फंडिंग कैसे की जा सकती है? 23
सीएडी की फंडिंग का आदर्श तरीका क्या है? 23
इंडिया का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? 23
रेग्युलेटर और पॉलिसीमेकर्स परेशान क्यों हैं? 23

Editorial and Corporate Office
Rajrooppur, Allahabad
RNI
UPHINDI/2005/26617
Publisher, Editor and Owner
Dheer Singh Rajput
Allahabad; Year 9, Issue 6, June, 2014
Place of Publication & Registerd Office
331è240 A, Stainly Road, Nayapura, Allahabad (UP)
Printing Press & Address
Academy Press Daraganj, Allahabad (UP)
Website : www.developindiagroup.com
E-mails : civilservicesminerva@gmail.com

संपादकीय और कॉरपोरेट ऑफिस
राजरूपपुर, इलाहाबाद
आरएनआई
UPHINDI/2005/26617
प्रकाशक, संपादक, और स्वामी
धीर सिंह राजपूत
इलाहाबाद, वर्ष 9, अंक 6, जून, 2014
प्रकाशन का स्थान और रजिस्टर्ड ऑफिस
331/240 ए, स्टैनली रोड, नयापुरा, इलाहाबाद (उ.प्र.)
प्रिंटिंग प्रेस का पता
एकेडमी प्रेस, दारागंज, इलाहाबाद (उ.प्र.)
वेबसाइट : www.developindiagroup.com
ई–मेल : civilservicesminerva@gmail.com

Read

Only in 500/- per year

Develop India

http://www.developindiagroup.co.in/

Develop India

Only in 500/- per year

Online Subscription

http://www.developindiagroup.co.in/

राष्ट्रीय समसामयिकी

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पेश किया मोदी सरकार का एजेंडा

भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 9 जून 2014 को संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए मोदी सरकार का एजेंडा पेश किया. इसमें आर्थिक सुधारों को गति देने, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने समेत सार्वजनिक क्षेत्र के खनन उद्योग में निजीकरण को प्रोत्साहन देने की बात भी कही गई. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने भाषण में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनने वाली नई सरकार की कई महत्वाकांक्षी नीतियों का जिक्र किया. इसमें नई सरकार के भारत में सौ नए शहरों के निर्माण और रेलवे नेटवर्क को मजबूत बनाने के लक्ष्य को रेखांकित किया गया. उन्होंने आगे कहा कि इसके साथ साथ लंबे समय से लटकी पड़ी बड़ी परियोजनाओं को तेजी से मंजूरी दी जाएगी.

वर्ष 2014 को विगत वर्षों की विभंजनकारी और टकराव की राजनीति से राहत देने वाला वर्ष बताते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि वह अपने साथी नागरिकों के विवेक की सराहना करते हैं, जिन्होंने ऐसे उदीयमान भारत में स्थिरता, ईमानदारी और विकास के लिए मत दिया, जिसमें भ्रष्टाचार का कोई स्थान न हो। उन्होंने कहा, आजादी के 75 साल पूरे होने पर यानी 2022 तक देश के प्रत्येक परिवार का अपना पक्का मकान होगा।

लोकसभा चुनाव के बाद बनी नरेंद्र मोदी सरकार के भावी कार्यक्रमों का खाका दर्शाने वाले राष्ट्रपति के इस अभिभाषण में कहा गया, जब देश अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करेगा तब प्रत्येक परिवार का अपना पक्का घर होगा जिसमें पानी का कनेक्शन, शौचालय सुविधाएं और चौबीसों घंटे विद्युत आपूर्ति तथा आवागमन की सुविधाएं होंगी। मुखर्जी ने केन्द्रीय कक्ष में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा, देश को ऐसी मजबूत और स्थिर सरकार की आवश्यकता है जो प्रभावी नेतृत्व प्रदान करे। इस वर्ष के प्रारंभ में गणतंत्र दिवस के अपने भाषण में मैंने आशा व्यक्त की थी

मिस्र में सैन्य प्रमुख अब्दुल फत्ताह अल सिसी ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली

मई में हुए चुनाव में भारी जीत हासिल करने वाले मिस्र के पूर्व सैन्य प्रमुख अब्दुल फताह अल सिसी ने 9 जून 2014 को देश के नये राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। पिछले साल इस्लामवादी नेता मोहम्मद मुरसी को हटाए जाने के करीब साल भर बाद हुए राष्ट्रपति चुनाव में 96.66 प्रतिशत वोट हासिल करने के बाद सिसी पिछले सप्ताह देश के राष्ट्रपति घोषित किये गए थे। शीर्ष संवैधानिक अदालत के जनरल असेंबली के सामने एक समारोह में उन्होंने चार वर्ष के कार्यकाल की शपथ ली। बाद में उन्हें 21 बंदूकों की सलामी दी गयी और फिर राष्ट्रगान हुआ।

वह मिस्र के सातवें राष्ट्रपति हैं। रविवार को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया। कम गहमागहमी वाले समारोह में प्रधानमंत्री इब्राहीम महलाब का समस्त कैबिनेट और सिसी की पत्नी व बच्चे उपस्थित थे। नीला सूट पहने सिसी ने हॉल में प्रवेश किया। उनके साथ निवर्तमान अंतरिम राष्ट्रपति अदले मंसूर थे। समारोह का टीवी पर सीधा प्रसारण हुआ। जहां कई विदेशी प्रतिनिधि उपस्थित होंगे।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव में उनकी सफलता के बाद उन्हें बधाई संदेश भेजा है।

कि 2014 विगत वर्षों की विभंजनकारी और टकराव की राजनीति से राहत देने वाला वर्ष होगा। उन्होंने कहा, आज यहां मैं अपने साथी नागरिकों के विवेक की सराहना करता हूं, जिन्होंने ऐसे उदीयमान भारत में स्थिरता, ईमानदारी और विकास के लिए मत दिया, जिसमें भ्रष्टाचार का कोई स्थान न हो। उन्होंने संगठित, सुदृढ और आधुनिक भारत... एक भारत श्रेष्ठ भारत.. के लिए मत दिया है।

मेरी सरकार इन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस महान देश की 125 करोड़ जनता के साथ मिलकर काम करेगी। मुखर्जी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि स्वतंत्रता के इतने दशकों बाद भी अल्पसंख्यक समुदाय गरीबी से पीड़ित है और सरकारी स्कीमों के लाभ उस तक नहीं पहुंचते हैं। राष्ट्रपति ने कहा, मेरी सरकार भारत की प्रगति में सभी अल्पसंख्यकों को बराबर का भागीदार बनाने के लिए कृतसंकल्प है।

मोदी सरकार का रोडमैप बताने वाले राष्ट्रपति के अभिभाषण में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना सरकार के लिए बड़ा उद्देश्य कहा गया। इसमें कहा गया, हम अपनी अर्थव्यवस्था को सतत उच्च विकास पर ले जाने के लिए मिल जुल कर कार्य करेंगे, महंगाई नियंत्रित करेंगे, निवेश चक्र में तेजी लाएंगे, रोजगार सृजन तेज करेंगे और अपनी अर्थव्यवस्था के प्रति घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय समुदाय का विश्वास बहाल करेंगे।

राष्ट्रपति ने 16वीं लोकसभा के चुनाव को उम्मीदों का चुनाव बताते हुए कहा कि यह हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण पड़ाव है। चुनावों में 66.4 प्रतिशत मतदाताओं की रिकॉर्ड भागीदारी और लगभग 30 वर्षों पश्चात किसी एक ही पार्टी को मिला स्पष्ट जनादेश लोगों की बढी हुई आकांक्षाओं और उनके इस विश्वास को दर्शाता है कि उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही पूरा किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने जाति, पंथ, क्षेत्र और धर्म की सीमाओं को तोडा है और उन्होंने सुशासन एवं विकास के पक्ष में एकजुट होकर निर्णायक मत दिया है।

लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, उनके मंत्रि परिषद सहयोगी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और विपक्ष के अन्य नेताओं ने राष्ट्रपति के 50 मिनट तक चले अभिभाषण को ध्यान से सुना। अभिभाषण के दौरान कई मौकों पर सदस्यों ने मेजें थपथपाकर राष्ट्रपति की घोषणाओं का स्वागत किया।

विदेश नीति के बारे में राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार की अपने अड़ोस पड़ोस के माहौल को शांतिपूर्ण और स्थिर रखने तथा आर्थिक रूप से जोडने की दिशा में प्रतिबद्धता और संकल्प को दर्शाती है जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र के सामूहिक विकास और समृद्धि के लिए अनिवार्य है। उन्होंने कहा, हम दक्षिण एशियाई नेताओं के साथ मिलकर सार्क (दक्षेस) को क्षेत्रीय सहयोग के प्रभावी साधन बनाने और वैश्विक मुद्दों पर सामूहिक आवाज बनने के लिए कार्य करेंगे।

राष्ट्रपति ने कहा, मेरी सरकार समाज के विकास और राष्ट्र की समृद्धि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करती है। वह संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि हाल ही में देश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की कुछ जघन्य घटनाएं हुई हैं। सरकार महिलाओं के विरूद्ध हिंसा को बिल्कुल सहन ना करने (जीरो टालरेंस) की नीति अपनाएगी और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दांडिक न्याय प्रणाली को समुचित रूप से मजबूत किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में घुसपैठ और गैर कानूनी प्रवासियों के मुद्दे को प्राथमिकता से निपटाया जाएगा तथा पूर्वोत्तर सीमा पर बाड लगाने के रूके संपूर्ण कार्य को शीघ्र पूरा किया जाएगा। मुखर्जी ने कहा कि ये सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किये जाएंगे कि कश्मीरी पंडित अपने पूर्वजों की भूमि पर पूर्ण गरिमा, सुरक्षा और सुनिश्चित जीविका के साथ लौटें।

नवनिर्वाचित सदस्यों का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने उनसे कहा कि हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम अपने नागरिकों की वजह से यहां हैं और उनकी सेवा करना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इस बार के आम चुनाव शांतिपूर्ण ढंग और सुचारू रूप से संपन्न होने का जिक्र करते हुए उन्होंने चुनाव आयोग और उससे जुडे सरकारी तंत्र को सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा, इन चुनावों में हमारे नागरिकों द्वारा दर्शाई गई अभूतपूर्व रूचि हमारे जीवंत लोकतंत्र की गहराती जडों का द्योतक है। उन्होंने कहा कि सरकार उसे मिले जनादेश को पूरा करने के लिए सही वातावरण तैयार करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके लिए सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' सिद्धांत को अपनाएगी। हम लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को पुनरू कायम करने के लिए साथ मिलकर कार्य करेंगे। 'मेरी सरकार न्यूनतम सरकार, अधिकतम सुशासन' के मंत्र पर कार्य करेगी।

अभिभाषण में कहा गया कि सरकार गरीबों के प्रति समर्पित है। गरीबी का कोई धर्म नहीं होता है। भूख का कोई पंथ नहीं होता है और निराशा का कोई भूगोल नहीं होता। हमारे सामने सबसे बडी चुनौती भारत में गरीबी के अभिशाप को समाप्त करना है। मेरी सरकार केवल निर्धनता उपशमन से संतुष्ट नहीं होगी बल्कि यह गरीबी का पूर्ण निवारण करने के लक्ष्य के प्रति वचनबद्ध है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार का दृढ मत के साथ कि विकास पर पहला हक गरीब का है, अपना ध्यान उन पर केन्द्रित करेगी, जिन्हें जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की तुरंत आवश्यकता है। सरकार सहानुभूति, सहायता और सशक्तीकरण द्वारा सभी नागरिकों को हर तरह की सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक उपाय करेगी। खाद्य पदार्थों की कीमतों को बढने से रोकने को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न कृषि एवं कृषि आधारित उत्पादों के आपूर्ति पक्ष को सुधारने पर बल दिया जाएगा। मेरी सरकार जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएगी। सरकार राज्यों की सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को अपनाते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करेगी। मेरी सरकार इस वर्ष सामान्य से कम मानसून की संभावना के प्रति सतर्क है और इसके लिए उपयुक्त योजनाएं तैयार की जा रही हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत संघीय व्यवस्था वाला देश है। परंतु काफी वर्षों से, इसकी संघीय भावना को कमजोर किया गया है। राज्यों और केन्द्र को सामंजस्यपूर्ण 'टीम इंडिया' के रूप में काम करना चाहिए। राष्ट्रीय मुद्दों पर राज्यों के साथ सक्रियता से कार्य करने के लिए केन्द्र सरकार राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर राज्यीय परिषद जैसे मंचों को पुनरू सशक्त बनाएगी। केन्द्र सहकारी संघवाद के जरिए राज्यों की त्वरित प्रगति में सहयाक बनेगा।

हर घर में बिजली

इस संदर्भ में राष्ट्रपति ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के कोयला खनन में तात्कालिक आधार पर निजीकरण की नीति अपनाएगी. उन्होंने कहा कि नई सरकार की कोशिश होगी कि हर भारतीय के घर में बिजली मुहैया हो सके.

राष्ट्रपति ने कहा, सरकार ब्रांड इंडिया को पाँच टी यानी ट्रेडिशन, टैलेंट, टूरिज्म, ट्रेड और टेक्नॉलजी के माध्यम से फिर से स्थापित करेगी.

आंतरिक सुरक्षा के मसले पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के साथ मिलकर दंगों के खिलाफ नीतियां बनाई जाएंगी.

आतंकवाद और दंगों के खिलाफ सरकार जीरो टालरेंस की नीति अपनाएगी और नशीले पदार्थों की तस्करी और साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए नया बुनियादी ढांचा निर्मित किया जाएगा.

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार क्लिक करें सार्क को पुनर्जीवित करेगी. राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार नेशनल वॉर मेमोरियल का निर्माण करेगी और समान रैंक के लिए समान पेंशन वाली योजना को लागू करेगी.

रिलायंस ही इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट

भारत में मीडिया क्षेत्र में सबसे बड़े सौदों में रिलायंस इंडस्ट्रीज टीवी क्षेत्र की सबसे बड़ी

कंपनियों में से एक नेटवर्क 18 मीडिया एंड इनवेस्टमेंट लिमिटेड (एनडब्ल्यू18) और इसकी सहायक कंपनी टीवी 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड में नियंत्रक हिस्सेदारी 4,000 करोड़ में खरीद रही है. अरबपति उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस ने गुरुवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि कंपनी के बोर्ड ने अधिग्रहण के लिए इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट (आईएमटी) को 4,000 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है.

रिलायंस ही इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट की संपत्तियों की एकमात्र लाभभोगी है.

एनडब्ल्यू18 का कारोबार डिजिटल इंटरनेट, ई कॉमर्स और प्रसारण के लिए विभिन्न सामग्री बनाने तक फैला है.

रिलायंस के बयान में कहा गया है, आईएमटी इस फंड का इस्तेमाल अधिग्रहण के लिए करेगा, जिससे नेटवर्क 18 में उसकी हिस्सेदारी 78 प्रतिशत और टीवी 18 में नौ प्रतिशत हो जाएगी.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जनवरी 2012 में नेटवर्क 18 समूह और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक सौदा किया था. इस सौदे के तहत रिलायंस को ईटीवी में अपनी आंशिक हिस्सेदारी बेचनी थी और बदले में वो नेटवर्क 18 समूह के वितरण और कंटेंट का इस्तेमाल कर पाती.

रिलायंस ने जो विज्ञप्ति जारी की है उसमें कहा गया है कि सेबी (सब्सटेंशियल एक्विजिशन एंड टेकओवर रेग्युलेशन) 2011 के नियमों के तहत आईएमटी एनडब्ल्यू18, टीवी18 और इंफोमीडिया प्रेस लिमिटेड के शेयरों के अधिग्रहण के लिए खुला ऑफर लाएगी.

कंपनी के अनुसार टेलीकॉम, वेब, डिजिटल कॉमर्स के एकीकरण के मार्फत यह अधिग्रहण रिलायंस के 4जी कारोबार में सहायक होगा.

अब रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह के पास इन डॉटकॉम, आईबीएन लाइव डॉटकाम, मनी कंट्रोल डॉटकॉम, फर्स्टपोस्ट डॉटकॉम, क्रिकेट नेक्स्ट डॉटइन, होम शॉप 18 डॉटकॉम, बुक माई शो डॉटकॉम के अलावा कलर्स, सीएनएन आईबीएन, सीएनबीसी, टीवी18, आईबीएन7 और सीएनबीसी आवाज जैसे चैनलों का स्वामित्व आ जाएगा.

अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी

मोदी की विदेश यात्राओं पर नजर

प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी सुदूर पूर्व जापान से सुदूर पश्चिम अमेरिका तक की यात्रा करने वाले हैं. लेकिन शुरुआत पड़ोसी देश भूटान से करेंगे. मोदी की विदेश यात्राओं से भारतीय अर्थव्यवस्था को खासी उम्मीद है.

भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि मोदी अगले महीने ही जापान की यात्रा पर जा सकते हैं. जापान ने इससे पहले उम्मीद जताई थी कि मोदी इसी महीने जापान आ सकते हैं लेकिन मोदी ने अपनी विदेश यात्राओं की शुरुआत पड़ोसी देश भूटान से करने का फैसला किया.

विदेश मंत्री के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने बताया, प्रधानमंत्री को जापान से जल्द से जल्द आने की दावत आई है और हो सकता है कि वह जुलाई में वहां जाएं. लेकिन पड़ोसी देश भारत की प्राथमिकता होंगे.

मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के अलावा भूटान और दूसरे दक्षिण एशियाई देशों के सरकार प्रमुखों को न्योता दिया था. जानकारों का कहना है कि एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने और चीन से प्रतिस्पर्धा करने के उद्देश्य से जापान भारत के साथ गठबंधन करना चाहता है.

जापान सरकार के प्रवक्ता योशीहीदे सूगा का कहना है, प्रधानमंत्री शिन्जो आबे ने भारत के नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जापान बुलाया है और अब दोनों देश इसके लिए योजना बना रहे हैं. भारत में मोदी की जीत के बाद दोनों नेताओं ने ट्विटर पर एक दूसरे को संदेश भेजा था.

पहली विदेश यात्रा

जापान के जीजी प्रेस ने रिपोर्ट दी थी कि मोदी सबसे पहले जापान की यात्रा करेंगे. इसके बाद ही भारत के विदेश मंत्रालय ने इस मामले में सफाई दी है. इस बीच रिपोर्ट है कि सितंबर में मोदी संयुक्त राष्ट्र के सालाना अधिवेशन में जाएंगे और इस दौरान उनकी मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से होगी.

जापान में ढांचागत संरचना का बड़ा उद्योग है और भारत अपने खस्ताहाल सड़कों और जर्जर इमारतों की वजह से उसका बड़ा बाजार बन सकता है. लेकिन जानकारों का कहना है कि भारत और जापान सिर्फ आर्थिक वजहों से एक साथ नहीं हैं. उन्हें जोड़ने वाला चीन है. दोनों ही देशों का चीन के साथ सीमाई विवाद है. चीन लगातार अपनी सैनिक क्षमता बढ़ा रहा है, जिससे भारत और जापान दोनों चिंतित हैं.

पूर्वी चीनी सागर में कई द्वीपों के मालिकाना हक को लेकर भी जापान का चीन के साथ विवाद चल रहा है. जबकि भारत और चीन के बीच 1962 में युद्ध हुआ, जिसके बाद से दोनों के बीच सरहदी विवाद जारी है.

अमेरिका का सवाल

इसके अलावा भूटान को भारत का ष्सदा सहयोगीष् का रुतबा प्राप्त है. चीन के साथ उसकी अनबन होती रहती है. जहां तक अमेरिका का सवाल है, वह जापान का अच्छा सामरिक साथी है. अमेरिका भी चीन के बढ़ते आर्थिक और सैनिक ताकत से चिंतित है और जापान और भारत की नजदीकी उसे पसंद आएगी.

हालांकि खुद अमेरिका का मोदी के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है. गुजरात के 2002 के दंगों की वजह से अमेरिका ने मोदी को 2005 से वीजा नहीं दिया है. दंगों के वक्त मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उनपर आरोप हैं कि उन्होंने इसे नियंत्रण करने में पूरी शक्ति नहीं लगाई. हालांकि किसी अदालत ने उन्हें कभी दोषी करार नहीं दिया है.

तिब्बत के लिए दूसरी मुहिम

चीन से अलग होने की मुहिम को नए सिरे से शुरु करने के लिए निर्वासन में रह रहे तिब्बती सरकार नेता इस हफ्ते दलाई लामा से मिल रहे हैं. इस मुहिम के लिए मीडिया अभियान भी शुरू किया जाएगा.

भारत के धर्मशाला शहर में तिब्बती नेता निर्वासन में रह रहे हैं. दलाई लामा बार बार कह चुके हैं कि उन्हें चीन से स्वतंत्रता नहीं, बल्कि स्वायत्तता चाहिए. इस बात को बेहतर ढंग से समझाने के लिए वे एक वेबसाइट शुरू करेंगे और सोशल वेबसाइटों से भी अपनी बात रखेंगे. वे ष्बीच का रास्ताष् निकालना चाहते हैं.

तिब्बतियों का मानना है कि चीन उनके धर्म और संस्कृति में दखल दे रहा है. इस मुद्दे को लेकर तिब्बतियों का लंबे वक्त से चीन के साथ संघर्ष चल रहा है. 2009 के बाद से करीब 100 तिब्बतियों ने इस मामले को लेकर आत्मदाह कर लिया है.

तिब्बतियों के निर्वासित सरकार के सूचना मंत्री डिक्की छोयांग का कहना है, हमने तिब्बतियों से अपील की है कि वे आत्मदाह न करें और हम चीनी सरकार से अपील करते हैं कि वे तिब्बतियों की बात सुनें और उनके खिलाफ दमनकारी कार्रवाई न करें.ष उन्होंने कहा, ष्हम अभियान चलाना चाहते हैं, जिससे साबित कर सकें कि इस मसले का समाधान मुमकिन है.

तिब्बत को चीन देश का हिस्सा बताता है. उसका दावा है कि उसने इलाके में आर्थिक विकास किया है. वह दलाई लामा पर भी सवाल उठाता आया है. दलाई लामा ने 1959 में नाकाम विद्रोह किया था, जिसके बाद उन्हें तिब्बत से भाग कर भारत जाना पड़ा. वह तब से वहीं रह रहे हैं. इस बीच उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है.

बीजिंग ने 2010 तक दलाई लामा के प्रतिनिधि से बात की है. लेकिन इसके बाद यह सिलसिला टूट गया. वह निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री लोबसांग सांगे से भी बात करने को राजी नहीं. दलाई लामा ने 2011 में राजनीतिक पदों से इस्तीफा दे दिया है. सांगे ने हालांकि अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है लेकिन उनमें दलाई लामा वाला करिश्मा नहीं है.

दलाई लामा का करिश्मा

हालांकि दलाई लामा ने सार्वजनिक जीवन से अलग होने का फैसला किया है. फिर भी गुरुवार को होने वाले कार्यक्रम में वह खास तौर पर शिरकत करेंगे. धर्मशाला में होने वाले इस आयोजन को लेकर तिब्बती ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना चाहते हैं.

सांगे जिस ष्बीच के रास्तेष् की बात करते हैं, अमेरिका भी उसकी तरफदारी करता है. राष्ट्रपति बराक ओबामा ने फरवरी में जब दलाई लामा से मुलाकात की थी, तो उन्होंने इस पर हामी भरी थी. हालांकि इस मुलाकात से चीन काफी नाराज हुआ था.

कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आधुनिक तिब्बती विषय के प्रोफेसर रॉबी बार्नेट का कहना है कि जब से दलाई लामा रिटायर हुए हैं, इस मुद्दे पर बात आगे नहीं बढ़ पाई है. बार्नेट का कहना है कि तिब्बती नेता अपने आलोचकों को शांत करने में नाकाम रहे हैं. ये आलोचक तिब्बत की पूर्ण स्वतंत्रता की बात करते हैं. उनका कहना है, ष्बात को हमेशा से संभव है लेकिन इसका सकारात्मक नतीजा तभी निकल सकता है, जब बातचीत करने वाले में अद्भुत क्षमता हो और तिब्बती पक्ष धैर्य रख सके और चीनी प्रशासन अपने रवैये को नरम करने के लिए तैयार हो.ष

चीन ने 2002 से 2010 के बीच दलाई लामा के दूत से नौ दौर की बातचीत की है. लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला और बाद में यह टूट गई. बार्नेट का कहना है कि तिब्बतियों को यह अच्छी तरह पता है कि उनके पास सीमित समय है क्योंकि दलाई लामा 78 साल के हो चुके हैं, मुद्दा यह है कि तिब्बतियों का आंदोलन दलाई लामा के बाद कैसे चलेगा और बीजिंग की ताकत बढ़ने के साथ क्या वह उनसे

बातचीत के लिए राजी भी होगा.

असद की बड़ी जीत

बशर अल असद तीसरी बार सीरिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं. गृह युद्ध से जूझ रहे देश में असद दिनों दिन कमजोर होते जा रहे हैं. ऐसे में चुनाव के नतीजे कितने कारगर होंगे, कहना मुश्किल है.

सीरिया के स्पीकर जिहाद लाहम ने चुनावी नतीजों का एलान करते हुए कहा, मैं सीरिया अरब गणतंत्र के राष्ट्रपति के तौर पर डॉ. बशर अल असद की पूर्ण बहुमत से जीत का एलान करता हूं. चुनाव में असद 88.7 फीसदी वोट मिले.

सर्वोच्च संवैधानिक अदालत के मुताबिक चुनाव में 73 फीसदी वोटिंग हुई. नतीजों को विरोधियों की कड़ी हार बताते हुए विदेश मंत्री फैजल मोकदाद ने कहा, परिणाम *उन लोगों को तगड़ा झटका हैं जो तीन साल से ज्यादा समय से आतंकवाद से लड़ रहे सीरिया के लोगों की क्षमता पर शक कर रहे थे.*

लेबनान के एक सीरिया समर्थक चौनल से बात करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि नतीजों से साफ हो गया है कि राष्ट्रपति अल असद पर लोगों को पूरा विश्वास है. उन्होंने नतीजों पर शक करने वालों की आलोचना भी की, ष्नतीजे दिखाते हैं कि सीरिया अरब गणतंत्र के लोग अपने संविधान और कानूनी दायित्वों का सम्मान करते हैं. ये पश्चिमी देशों के चुनावों से भी बेहतर हैं जो खाड़ी के देशों के पैसे और प्रोपेगंडा पर आधारित हैं.

नतीजों का एलान होते ही राजधानी दमिश्क की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग जश्न मनाने लगे. सीरियाई टेलीविजन में अल असद को भी नाचते हुए दिखाया गया. लेबनान की राजधानी बेरुत में भी जश्न का माहौल दिखा. लेबनान का आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह सीरिया में अल असद की सेना की मदद कर रहा है.

सीरिया में तीन साल पहले अरब वसंत के बाद असद विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए. असद पर आरोप हैं कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों को सेना के सहारे दबाने की कोशिश की. धीरे धीरे प्रदर्शन सशस्त्र विद्रोह में बदल गए. अब वहां अल कायदा से जुड़े बर्बर आतंकवादी संगठन भी सरकारी सेना के खिलाफ लड़ रहे हैं. वंशवादी

जी7 शिखर सम्मलेन

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भले ही जी7 शिखर सम्मलेन से बाहर हैं लेकिन वहां हुई चर्चा में वही छाए हुए हैं. यूरोप और अमेरिका रूस पर नए प्रतिबंध लगाने के बारे में सोच रहे हैं. बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में चल रहे जी7 देशों के शिखर सम्मलेन में यूक्रेन का मुद्दा अहम रहा. अमेरिका, कनाडा, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने मिल कर रूस से आग्रह किया है कि हाल में यूक्रेन में हुए चुनावों को मान्यता दे और सीमा से अपनी सेनाएं हटाए. सभी सात देश इस बात को ले कर एकमत दिखे कि रूस को यूक्रेन में हथियारों की आवाजाही को रोकना होगा.

फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसोआ ओलांद ने कहा कि बैठक के बाद संदेश साफ है. पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, वहां हम सात लोग थे, आठ नहीं. हम सब लोग एक ही आवाज में बोल रहे थे और एक ही नतीजे पर पहुंचे हैं. पुतिन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, हर किसी तक यह संदेश पहुंचना चाहिए, उन लोगों तक भी जो इस बैठक में नहीं थे.

ओबामा की सख्ती

मार्च में जी8 के सात देशों ने यूक्रेन विवाद के कारण रूस में होने वाले शिखर सम्मेलन से अपने को बाहर कर लिया और खुद अपनी जी7 सम्मेलन करने का फैसला किया. हालांकि पुतिन ने बैठक में ना बुलाए जाने पर कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी है, पर बैठक से पहले उन्होंने यह जरूर कहा कि वह बातचीत के लिए राजी हैं. जहां यूरोपीय देश उन्हें बातचीत का मौका देना चाह रहे हैं, वहीं अमेरिका का रुख बेहद कड़ा है. ओबामा की फिलहाल पुतिन से मिलने की कोई योजना नहीं है. मंगलवार को उन्होंने पोलैंड में कहा कि पूर्वी यूरोप की स्थिति को देखते हुए वे नाटो देशों में सेना की तैनाती के लिए नए कदमों के बारे में विचार कर रहे हैं.

वहीं दूसरी ओर फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसोआ ओलांद, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन और जर्मनी की चांसलर अंगेला मैर्केल पुतिन के साथ शांति वार्ता की तैयारी में हैं. इसी सप्ताहांत फ्रांस में डीडे की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर उनकी पुतिन से मिलने की योजना है. दरअसल यूरोपीय देश तेल और गैस के लिए रूस पर निर्भर हैं. इसी वजह से वे चाह कर भी मॉस्को से बहुत ज्यादा दूरी नहीं बना पा रहे हैं. वहीं अमेरिका की रूस पर ऐसी कोई निर्भरता नहीं है.

पुतिन पर निर्भरता

यूरोप और अमेरिका की स्थिति में अंतर के बावजूद सभी देश रूस पर नए प्रतिबंध लगाने को ले कर एकमत हैं. जर्मन चांसलर अंगेला मैर्केल ने कहा, आज शाम यहां जो चर्चा हुई उसमें हमने अपनी प्राथमिकता तय की है कि हम उनसे चर्चा करना चाहते हैं. हमारे लिए सबसे जरूरी है कि यूक्रेन जल्द ही सही राह पर आ जाए.

जी7 देशों के लिए चिंता का एक बड़ा विषय यह भी है कि सीरिया, ईरान और अफगानिस्तान जैसे देशों के विवादित मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैसले लेने के लिए भी उसे रूस की जरूरत है. ऐसे में वे पुतिन को पूरी तरह दरकिनार नहीं कर सकते. जी7 की दो दिवसीय बैठक में आज सातों देश अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, पर्यावरण नीति और विकास के मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं.

सत्ता के खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शन अब खो चुके हैं, उनकी जगह मजहबी ताकतों ने ले ली है. एक तरफ असद और उनकी मदद करते आतंकवादी तो दूसरी तरफ राजनीतिक विद्रोही और जिहादी हैं. देश का उत्तरी इलाका करीब करीब विद्रोहियों के कब्जे में है. दक्षिण में भी उनका नियंत्रण कसता जा रहा है. संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया के संघर्ष में अब तक डेढ़ लाख लोग मारे जा चुके हैं.

भारत और विश्व

भारत–श्रीलंका में मछुआरों का मुद्दा

श्रीलंका में आए दिन भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी द्विपक्षीय संबंधों के लिए गंभीर चुनौती बन गया है लेकिन इस बहाने जो राजनीति हो रही है, उसमें गरीब मछुआरे पिस रहे हैं और उनके समक्ष रोजी रोटी का संकट बढ़ रहा है.

श्रीलंका के मत्स्य पालन विभाग का कहना है कि भारतीय मछुआरे गहरे समुद्र में संगठनात्मक रूप से मछली पकड़ रहे हैं और एक रणनीति के तहत समुद्री सीमा का उल्लंघन कर रहे है. श्रीलंका के मुताबिक वे हर साल उसकी समुद्री सीमा में घुस कर करीब साढ़े छह करोड़ किलो मछली पकड़ रहे हैं जिससे उसे भारी नुकसान हो रहा है. इस समस्या के हल के लिए उसने यूरोपीय संघ पर भी टकटकी लगाई लेकिन वहां से उसे कोई जवाब नहीं मिला.

भारतीय और श्रीलंका की मछलियों का सबसे बड़ा बाजार यूरोपीय संघ है. श्रीलंका ने यूरोपीय संघ में अनौपचारिक शिकायत की थी कि वह भारत पर अवैध मछली पकड़ने पर रोक लगाने के लिए दबाव बनाए लेकिन संघ का कहना है कि इस तरह के द्विपक्षीय मामलों में हस्तक्षेप का उसे अधिकार नहीं है. श्रीलंका का आरोप है कि उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों के अनुसार भारतीय मछुआरे संगठित रूप से यह काम कर रहे हैं और यह रुकना चाहिए.

शपथ ग्रहण में आए राजपक्षे

भारत में आम चुनाव के बाद पड़ोसी देशों के साथ संबंध बेहतर बनाने के लिए अपने शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (दक्षेस) के सभी शासनाध्यक्षों को बुलाया और सभी ने इस समारोह में शिरकत की. इस दौरान श्रीलंका के साथ ही पाकिस्तान ने ष्परस्पर संबंधों को बेहतर बनाने के लिएष भारतीय मछुआरों को रिहा किया. भारत की नई सरकार ने साथ दोनों पड़ोसी मुल्कों के संबंध मधुर बनाने की यह बेहतर पेशकश थी और भारत ने इसका स्वागत किया.

भारतीय मछुआरों की दिक्कतें

श्रीलंका का कोई राष्ट्रपति पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ. राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे जब शपथ ग्रहण समारोह के अतिथि थे, तमिलनाडु के एमडीएमके नेता वाइको दिल्ली के जंतर मंतर पर उनकी भारत यात्रा के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे. तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता विरोध स्वरूप शपथ समारोह में शामिल नहीं हुईं. डीएमके नेता एम करुणानिधि को भी मछुआरों के नाम पर अपनी राजनीति करनी थी इसलिए वह भी समारोह में नहीं आए. तमिल संगठन तो इस पर लगातार विरोध कर रहे थे.

भारतीय मछुआरों का आरोप

तमिल मछुआरा संगठनों का आरोप है कि उन्हें मादक पदार्थ अधिनियम के तहत श्रीलंका की जेलों में ठूंसा जाता है. तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता तो आए दिन इस मामले में प्रधानमंत्री को पत्र लिख कर अपने राज्य में सुर्खियां बटोरती हैं. इस बहाने वह मछुआरों को भरोसा दिलाती हैं कि वह उनकी हितैषी हैं लेकिन यदि वह सचमुच हितैषी होतीं तो दिल्ली आकर राजपक्षे से बात करतीं और समस्या का समाधान निकालने की पेशकश करतीं. ऐसा लगता है कि सभी राजनीतिक फायदा उठाने की कवायद कर रहे हैं.

भारतीय मछुआरों के लिए गहरे समुद्र का कच्चाथीवी द्वीप सबसे ज्यादा संकट वाला इलाका बना हुआ है. भारतीय मछुआरे उसे अपनी सीमा समझते हैं लेकिन श्रीलंका की नौसेना उसे अपना हिस्सा बताती है और उस द्वीप पर मछली पकड़ रहे मछुआरों को पकड़ कर श्रीलंका ले जाती है. एक सूचना के अनुसार इस द्वीप को भारत का हिस्सा समझते हुए भारतीय मछुआरे कई बार नौसैनिकों से भिड़ जाते हैं. इस संघर्ष में अब तक करीब 350 भारतीय मछुआरे मारे जा चुके हैं.

कहां है विवादित द्वीप कच्चाथीवी

कच्चाथीवी द्वीप निर्जन है. वहां कोई बस्ती नहीं. इस द्वीप को भारत ने एक समझौते के तहत 1974 में श्रीलंका को सौंप दिया था. बार बार विवाद का कारण बन रहे इस द्वीप को श्रीलंका सरकार ने 2009 में यह कहते हुए पवित्र भूमि घोषित किया कि यह जमीन धार्मिक भाव से दी गई है. श्रीलंका ने कहा कि उस समय जयललिता मुख्यमंत्री नहीं थीं और उन्होंने श्रीलंका के तमिलों की सहानुभूति अर्जित करने के लिए कच्चाथीवी द्वीप श्रीलंका को सौंपने का समर्थन किया था.

फिलहाल जरूरत मछुआरों की समस्या के समाधान की है और दोनों देशों को मछुआरों के हितों के लिए समुद्री सीमा के विवाद को सुलझाने के लिए तेजी से कदम उठाने होंगे ताकि मछुआरों की आजीविका पर असर न पड़े.

भारत–चीन संबंध

चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत की नई सरकार के साथ उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेने दिल्ली आए हुए हैं. चीनी अखबारों ने दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंधों का स्वागत किया है. वांग यी ने 8 जून को भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की. मुलाकात के दौरान व्यापार और निवेश सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को सुधारने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा की गई.

उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस साल भारत दौरे पर आने की घोषणा की है.

भारत के नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनावों में भारी जीत हासिल की.

मोदी ने वादा किया कि वे अपने कार्यकाल के दौरान अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और चीन के साथ संबंधों को आगे ले जाएंगे.

आर्थिक सहयोग

चीन के प्रमुख अखबार श्यूथ डेलीश का मानना है कि भारत की कमजोर हो रही अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत करने का काम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्णतः संभव है.

"चीन–भारत मुकाबला बिलकुल फुटबॉल मैच की तरह है. चीन मैच के पहले हाफ में बढ़त लिए हुए है. मोदी युग आने के कारण भारत की शुरुआत मैच की दूसरे हाफ में हो रही है. कमजोर शुरुआत के बावजूद ये पूरी तरह संभव है कि भारत पहले के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करे."

चाइना इंस्टीच्यूट ऑफ कंटेंपोरेरी इंटरनेशनल रिलेशन में दक्षिण एशिया मामलों के विशेषज्ञ ने चाइना डेली को बताया कि भारत चीन से श्सबकश ले.

भारतीय अर्थव्यवस्था चीन–भारत के आपसी आर्थिक सहयोग के बल पर ही आगे बढ़ सकती है. साथ ही, ये भी जरूरी है कि मोदी चीन के सुधार के अनुभवों और खुली रणनीति से सबक ले.

चीनी इंटरनेट पर जारी एक लेख में कहा गया है कि चीन और भारत दोनों ने अंतरराष्ट्रीय मामलों में एक ही दृष्टिकोण अपनाया है, और इसलिए दोनों देशों के बीच किसी तरह के मतभेद की कोई जमीन नहीं बचती.

चीन–भारत मुकाबला बिलकुल फुटबॉल मैच की तरह है. चीन मैच की पहली पारी में बढ़त लिए हुए है. मोदी युग आने के कारण भारत की

शुरूआत मैच की दूसरी पारी में हो रही है. कमजोर शुरूआत के बावजूद ये पूरी तरह संभव है कि भारत पहले के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करे. लेख में इस बात पर भी चर्चा की गई है कि जापान भी भारत के साथ नजदीकी संबंध स्थापित करना चाहता है, लेकिन साथ में लेख ये भी कहता है कि भविष्य में चीन–भारत संबंध नई उंचाइयों को छूने वाले हैं.

क्षेत्रीय सुरक्षा और संप्रभुता

इंटरनेट पर जारी इस लेख में कहा गया है, "चीन–भारत के आर्थिक सहयोग को सुस्त वैश्विक अर्थव्यवस्था और करीब लाएगी लेकिन यदि जापान के कारण चीन–भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों में किसी तरह के टकराव के हालात पैदा होते हैं तो इससे चीन के साथ ही साथ भारत के विकास में भी रुकावट आएगी."

क्षेत्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के मामले में, विशेषकर पश्चिमी चीन के लिए, भारत एक महत्वपूर्ण कारक है. भारत को भी विकास के लिए जरूरी सुरक्षा के माहौल को बनाने और कायम रखने के लिए चीन के सहयोग की जरूरत है.

भारत के विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बांग्लादेश की तीन दिवसीय राजकीय यात्रा संपन्न

भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बांग्लादेश की तीन दिवसीय राजकीय यात्रा 27 जून 2014 को संपन्न हुई. यह यात्रा सुषमा स्वराज की विदेश मंत्री के रूप में पहली विदेश यात्रा है. यह एक सद्भावना यात्रा थी. सुषमा स्वराज की यह यात्रा संतोषजनक एवं लाभप्रद रही. सुषमा स्वराज ने यह यात्रा बांग्लादेश के विदेश मंत्री अबुल हसन महमूद अली के निमंत्रण पर की.

वह राष्ट्रपति अब्दुल हामिद, प्रधानमंत्री शेख हसीना, अपने समकक्ष एएच महमूद अली, विपक्ष की नेता रौशन इरशाद और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया सहित शीर्ष बांग्लादेशी नेताओं से मुलाकात कीं. इस यात्रा के दौरान बांग्लादेश के विदेश मंत्री एएच महमूद अली और शुषमा स्वराज के बीच हुई बैठक में उदार वीजा नियमों के फैसले के साथ–साथ तीस्ता नदी जल समझौता, सीमा तथा भूमि अदला–बदली समझौता 'एलडीए' सहित आपसी सहयोग बढ़ाने के सभी उभयद्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई.

इस यात्रा के दौरान सुषमा स्वराज ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री तथा बांग्लादेश नेशनल पार्टी की अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया तथा बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति हुसैन मुहम्मद इरशाद की पत्नी और विपक्षी दल 'जातीय पार्टी' की नेता रोशन इरशाद से भी भेंट की.

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने स्वदेश रवाना होने से पहले ढाका स्थित ढाकेश्वरी मंदिर गईं और वहां दर्शन तथा पूजा–अर्चना भी की.

इस यात्रा के दौरान दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा, परिवहन संपर्क व जनता के बीच आपसी संपर्क बढ़ाए जाने पर सहमति हुई. इस सहमति से निश्चित तौर पर क्षेत्रीय सहयोग बढ़ेगा तथा पूर्वोत्तर में भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर भी भारत को बांग्लादेश से और सहयोग मिलेगा.

बातचीत के दौरान सुषमा स्वराज ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को सौंपी. भारत के राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने अपनी पहली विदेश यात्रा पर वर्ष 2013 में ढाका गए थे.

अर्थव्यवस्था/वाणिज्य

मोर पावर टू इंडियाः द चैलेंज ऑफ डिस्ट्रिब्यूशन रिपोर्ट

विश्व बैंक ने भारत में ऊर्जा क्षेत्र में सुधार पर 24 जून 2014 को मोर पावर टू इंडियाः द चैलेंज ऑफ डिस्ट्रिब्यूशन नामक एक रिपोर्ट जारी की. इसे नई दिल्ली में जारी किया गया. यह रिपोर्ट भारत सरकार के अनुरोध पर किए गए अध्ययन के आधार पर बनाया गया है.

रिपोर्ट में भारत के ऊर्जा क्षेत्र की पहुंच, उपयोगिता प्रदर्शन और वित्तीय स्थिरता के प्रमुख क्षेत्रों की समीक्षा की गई है. इसमें उपभोक्ताओं तक बिजली के वितरण को इस क्षेत्र की सबसे कमजोर कड़ी बताया गया है.

रिपोर्ट में सेवा को उच्च स्तर तक ले जाने के लिए इस क्षेत्र को बाहरी हस्तक्षेप और नियामकों से मुक्त करने, जवाबदेही बढ़ाने और इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की सिफारिश की गई है.

मुख्य तथ्य

- भारत की वार्षिक प्रति व्यक्ति सालाना बिजली खपत करीब 800 किलोवाट की है जो दुनिया में सबसे कम है.
- साल 2011 में ऊर्जा क्षेत्र में कुल घाटा 1. 14 ट्रिलियन रुपयों का था. ये घाटे बहुत बड़े हैं जो वितरण कंपनियों (डिसकॉम्स) और बहुत ज्यादा उपयोगिताओंदृ राज्य बिजली बोर्डों (एसईबी) और राज्य बिजली विभागों के बीच केंद्रित है.
- संचित घाटे की वजह से बिजली क्षेत्र का ऋण 2011 में 3.5 ट्रिलियन रुपये था जो भारत के जीडीपी का 5 फीसदी के बराबर है.
- 2011 में इस क्षेत्र का करीब 60 फीसदी संचित घाटा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और झारखंड से हुआ. उत्तर प्रदेश अकेले ही 40 फीसदी संचित घाटे के लिए जिम्मेदार है.
- हालांकि ग्रीड कनेक्टिविटी बढ़ी है फिर भी विद्युतीकृत गांवों के 200 मिलियन से अधिक लोग बिना बिजली को रहने के लिए मजबूर हैं.
- भारत में व्यावसायिक प्रतिष्ठान में बिजली का कनेक्शन लेने के लिए सात प्रक्रियाएं और 67 दिन का समय लगता है. चीन में यह 28 दिन में, थाइलैंड में 35 दिन और सिंगापुर में 36 दिनों में हो जाता है.
- 2010 में भारत भर में घरेलू बिजली आपूर्ति का करीब 87 फीसदी रियायती था. 2010 में आधे से भी अधिक रियायती भुगतान (52फीसदी) देश के सबसे अमीर 40 फीसदी परिवारों को चला गया.

ऊर्जा क्षेत्र में घाटे के लिए जिम्मेदार कारक

- बिजली खरीदने के लिए डिसकॉम की लागत राजस्व की तुलना में तेजी से बढी है.
- ईंधन की कमी और जनरेटर और पीढ़ी अक्षमताओं के लिए महंगा ईंधन आयात करने की जरूरत.
- पिछले कुछ वर्षों से बढ़ते ब्याज खर्च और शुल्कों का लागत के साथ तालमेल नहीं है.
- बिलों की कम वसूली और वसूली में देरी.
- खरीदी गई बिजली के पांचवे हिस्से से भी अधिक उपभोक्ताओं द्वारा बर्बाद कर दिया जाता है.

सिफारिशें

अगर 2019 तक भारत को विकास के उच्च पथ पर लाना है और सभी को बिजली मुहैया करानी है तो भारत में बिजली वितरण के क्षेत्र में व्यापक सुधार करने होंगे. रिपोर्ट में दी गई मुख्य सिफारिशें हैं

- राज्य सरकारों को जब वे मुफ्त बिजली आपूर्ति का आदेश देते हैं, समय पर पारदर्शिता के साथ और पूरे सब्सिडी का भुगतान करना चाहिए.
- राज्य सरकारों को सब्सिडी के लक्ष्य में सुधार लाना चाहिए ताकि संसाधन बर्बाद न हो और वास्तव में गरीबों तक पहुंच सके.
- जनोपयोगी सेवाओं को सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त करना चाहिए और उसका प्रबंधन पेशेवर तरीके के करना चाहिए. निगमीकरण के बावजूद उपोगिता बोर्ड में राज्यों का प्रभुत्व है और उनका मूल्यांकन शायद ही कभी उनके प्रदर्शन के आधार पर होता है
- कुशल संचालन के लिए बैंकोंध उधारदाताओं को जवाबदेह होना चाहिए और जो भरोसे के लायक नहीं हो उनपर इसे नहीं छोड़ना चाहिए.
- नियामकों को प्रभावी लागत, सेवा मानकों पर पकड़ और निर्णय लेने के लिए उम्मीद के मुताबिक वातावरण पैदा करने के लिए शुल्कों में पारदर्शिता के साथ संसोधन करना चाहिए.
- ग्रहकों को इस्तेमाल की जाने वाली बिजली के लिए ही भुगतान करना पड़े और नियामक एवं राज्य सरकारें बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता के प्रति जवाबदेह हों.
- केंद्र सरकार को भविष्य में कोई बेलआउट नहीं देना चाहिए, नियामकों को स्वायतता और पर्याप्त संसाधन देना चाहिए और उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें ही जिम्मेदार बनाना चाहिए.

विश्व निवेश रिपोर्ट 2014

24 जून 2014 को व्यापार और विकास पर हुए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) ने विश्व निवेश रिपोर्ट 2014 जारी की. 2012 में गिरावट के बाद, 2013 में वैश्विक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) में 9 फीसदी की बढ़ोतरी हुई जिसके आने वाले वर्षों में जारी रहने की उम्मीद है.

भारत और विश्व निवेश रिपोर्ट 2014

- बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा निवेश के लिए सबसे पसंदीदा जगहों की सूची में भारत फिसलकर चौथे स्थान पर आ गया है.
- दूसरी तरफ विश्व के सबसे आकर्षक निवेश स्थान के तौर पर चीन ने अपनी जगह बनाई हुई है. दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया है.
- 2013 में भारत बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा विश्व का तीसरा सबसे आकर्षक निवेश स्थान घोषित किया गया था. 2005, 2006, 2007, 2008 और 2010 में भारत इस सूची में दूसरे स्थान पर था.
- 2013 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 17 फीसदी का इजाफा हुआ और यह 28 अरब डॉलर पर पहुंच गया.
- 2013 में अधिकतम एफडीआई हासिल करने वाले विश्व के शीर्ष 20 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की सूची में भारत का स्थान 14वां था.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी)–सी23 के सफल प्रक्षेपण

भारतीय रॉकेट ने 30 जून 2014 को पांचों विदेशी उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। रॉकेट प्रक्षेपण के दौरान श्रीहरिकोटा में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारतीय अंतरिक्ष क्षमता को वैश्विक मान्यता करार दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी)–सी23 के सफल प्रक्षेपण के बाद कहा, मेरा मानना है कि प्रौद्योगिकी मौलिक रूप से आम लोगों से जुड़ी हुई है। यह उनकी जिंदगी बदल सकती है।

प्रधानमंत्री ने कहा, हमने चांद पर यान भेजा और अब मंगल की तरफ यान जा रहा है। मैं इस घटना का साक्षी बन कर सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं।

उन्होंने इसे भारतीय अंतरिक्ष क्षमता को वैश्विक मान्यता करार दिया जो अटल बिहारी वाजेपयी के दृष्टिकोण से प्रेरित है। 44.4 मीटर लंबे और 230 टन भार वाले ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी)–सी23 का सोमवार सुबह 9.52 बजे को प्रक्षेपण किया गया।

पीएसएलवी के मुख्य उपग्रह में फ्रांस का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एसपीओटी–7 है। इसके अतिरिक्त जर्मनी का 14 किलोग्राम भार वाला एआईएसएटी, कनाडा का 15–15 किलोग्राम भार वाला एनएलएस7.1 (सीएएन–एक्स4) व एनएलएस7.2 (सीएएन–एक्स5) और सिंगापुर का सात किलोग्राम वजन वाला वीईएलओएक्स–1 उपग्रह शामिल है।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ई.एल.एल.नरसिंम्हन, मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू, अंतरिक्ष विज्ञानी और अन्य आगंतुक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) के रॉकेट अभियान नियंत्रण कक्ष में मौजूद थे।

यह मोदी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के सत्ता में आने के बाद इसरो का पहला अंतरिक्ष अभियान है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को उनके साथ साझा करनी चाहिए, जिनके पास यह सुविधा उपलब्ध नहीं। उन्होंने अफगानिस्तान और अफ्रीका के लिए टेलीमेडिसीन प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के प्रावधान की बात भी कही।

इसरो अधिकारी 20 मिनट के इस महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अभियान की बड़ी सफलता की उम्मीद कर रहे हैं।

उड़ान के 18 मिनट बाद रॉकेट से पहला व सबसे वजनदार उपग्रह स्पॉट–7 इससे अलग हुआ।

भारत ने 2012 में एसपीओटी–6 उपग्रह को अंतरिक्ष की केंद्र में स्थापित किया था। एसपीओटी–7 एसपीओटी श्रृंखला का अगला उपग्रह है।

इसके बाद इसने एआईएसएटी (जर्मनी), एनएलएस 7.1 एवं एनएलएश 7.2 (कनाडा) और वीईएलओएक्स–1 (सिंगापुर) को कक्षा में स्थापित किया।

भारत ने 1999 से लेकर अब तक पीएसएलवी के जरिये 35 विदेशी उपग्रह अंतरिक्ष के केंद्र में स्थापित किए हैं। इस नए अभियान के जरिये इसकी संख्या 40 हो जाएगी।

भारत ने अपने अंतरिक्ष अभियान की शुरूआत 1975 में रूसी रॉकेट के जरिये आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कर की थी। चांद व मंगल अभियान सहित भारत ने अपने 100 से अधिक अंतरिक्ष अभियान पूरे कर लिए हैं।

पी.एस.एल.वी.

ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान या पी.एस.एल.वी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संचालित एक उपभोजित प्रक्षेपण प्रणाली है। भारत ने इसे अपने सुदूर संवेदी उपग्रह को सूर्य समकालिक कक्षा में प्रक्षेपित करने के लिये विकसित किया है। पीएसएलवी के विकास से पूर्व यह सुविधा केवल रूस के पास थी। पीएसएलवी छोटे आकार के उपग्रहों को भू–स्थिर कक्षा में भी भेजने में सक्षम है। अब तक पीएसएलवी की सहायता से 64 अन्तरिक्षयान (29 भारतीय, 35 अन्तरराष्ट्रीय) विभिन्न कक्षाओं में प्रक्षेपित किये जा चुके हैं। इससे इस की विश्वसनीयता एवं विविध कार्य करने की क्षमता सिद्ध हो चुकी है।

मंगल यात्रा के लिए उड़ी नासा की उड़नतश्तरी

अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी (नासा) ने मंगल ग्रह पर भविष्य में यान को उतारने की तकनीक के संबंध में सफल परीक्षण किया है.

उड़नतश्तरी के आकार के इस यान को गैस के गुब्बारे की मदद से ऊंचाई पर भेजा गया.

इसका मकसद एक नए तरह के पैराशूट का परीक्षण था जो मंगल ग्रह की सतह पर अंतरिक्ष यान उतारते समय उसे धीमा करने में मददगार हो सके. इसके साथ इसमें एक हाव से फूलने वाला केवलर रिंग भी लगा था.

परीक्षण में पैराशूट के अलावा बाकघ सभी उपकरणों ने सही तरीकध् से काम किया. पैराशूट पूरी तरह से खुलने में नाकाम रहा.

यह परीक्षण हवाई क्षेत्र से किया गया था.

इससे पहले जिस लो–डेंसिटी सुपरसोनिक डेएक्सीलेरेटर (एलडीएसडी) अंतरिक्ष यान का परीक्षण किया गया, वह उड़ान के बाद प्रशांत महासागर में गिर गया.

नासा को उम्मीद है कि इससे भविष्य में मंगल पर अधिक वजन वाले यानों को उतारने में मदद मिल सकेगी.

फिलहाल वजन ले जाने की क्षमता डेढ़ टन के आसपास है. अगर इंसान मंगल तक पहुंचना

सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र

सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का प्रक्षेपण केंद्र है। यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरीकोटा में स्थित है, इसे श्रीहरीकोटा रेंज या श्रीहरीकोटा लॉंचिंग रेंज के नाम से भी जाना जाता है। 2002 में इसरो के पूर्व प्रबंधक और वैज्ञानिक सतीश धवन के मरणोपरांत उनके सम्मान में इसका नाम बदला गया।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 12 सितम्बर, 2013 को सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र, श्रीहरिकोटा में प्रक्षेपण यान की असेम्बली के लिए दूसरे भवन के निर्माण की मंजूरी दी। इस पर 363.95 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी, जिसमें सात करोड़ रुपये का खर्च विदेशी मुद्रा में होगा। इस दूसरी बिल्डिंग के उपलब्ध हो जाने से पीएसएलवी और जीएसएलवी की प्रक्षेपण फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। यह जीएसएलवी एमके–III के एकीकरण के लिए वर्तमान व्हीकल असेम्बली बिल्डिंग को अतिरिक्त सुविधा मुहैया करायेगी। तीसरे प्रक्षेपण पैड तथा भविष्य में सामान्य यान प्रक्षेपण के लिए भी इससे काफी सुविधा मिलेगी।

चाहते हैं, तो इस क्षमता को कम से कम 10 टन ले जाना होगा.

इस उड़ान के डॉटा रिकॉर्डर का पता लगाने के लिए कई दल रवाना किए गए हैं.

हीलियम वाले गुब्बारे को अमरीकी नौसेना की प्रशांत महासाहर क्षेत्र में मौजूद कुई मिसाइल रेंज फैसिलिटी से कघ्रीब 35 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंचने में दो घंटे का वकघ्त लगा.

अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी, नासा, उड़न तस्तरी जैसी तकनीक का परीक्षण

परीक्षण से पहले नासा के इंजीनियरों ने कहा था कि उनको इस परीक्षण उड़ान से उपयोगी आंकड़े मिलेंगे. अगले साल हवाई में इस परियोजना के तरह दो और परीक्षण होने की उम्मीद जताई जा रही है.

पर्यावरण/पारिस्थितिकी

द इंवायरमेंट क्राइम क्राइसिस रिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) ने 24 जून 2014 को कीनिया के नैरोबी में हुए पहले संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन में द इंवायरमेंट क्राइम क्राइसिस नाम से रिपोर्ट जारी की. यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) और इंटरपोल द्वारा त्वरित प्रतिक्रिया आकलन है. रिपोर्ट के मुताबिक, हर वर्ष होने वाला 213 अरब अमेरिकी डॉलर का वैश्विक पर्यावरण अपराध अपराधियों, नागरिक सेना और आतंकवादी समूहों को वित्तीय मदद पहुंचा रहा है और कई देशों की सुरक्षा और सतत विकास के लिए खतरा बन गया है. यह 135 अरब अमेरिकी डॉलर सके वैश्विक विकास सहायता के बराबर है.

वनस्पतियों और जीवों का अवैध व्यापारः

- जंगली हाथी के मामले में, 2002 और 2011 के बीच इनकी जनसंख्या में अनुमान के अनुसार 62 फीसदी की कमी आई है. एशियाई स्रोतों से हासिल किए जाने वाले हाथी दांतों के अलावा अवैध शिकार से हासिल किए गए कच्चे अफ्रीकी हाथी दातों की कीमत एशिया में 165 मिलियन डॉलर से लेकर 188 मिलियन डॉलर है.
- विभिन्न स्रोतों के अनुमान के मुताबिक सालाना 7 अरब डॉलर से 23 अरब डॉलर का कारोबार है वनस्पतियों और जीवों का अवैध व्यापार (मछली पकड़ने और लकड़ी काटने के अलावा) का.
- रूढ़ावादी अनुमानों के मुताबिक बड़े वानरों के अवैध शिकार में भी बढ़ोतरी हुई है. 2005 से 2011 के बीच कमदृ सेदृ कम 643 चिंपैंजी, 48 बोनोबोस, 98 गोरिल्ला और 1019 ओरैंगूटान के अवैध शिकार होने का अनुमान है. इस दौरान बड़े वानरों के अवैध शिकार का वास्तविक आंकड़ा करीब 22000 है.
- राइनों के अवैध शिकार का 94 फीसदी इनके सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिम्बाबे और दक्षिण अफ्रीका में होता है. यहां, संगठित गिरोहों की भागीदारी की वजह से 2007 में जहां अवैध शिकारों की संख्या 50 से भी कम थी, 2013 में यह 1000 से भी ज्यादा हो गई. पिछले वर्ष अवैध शिकार से हासिल हुए राइनों की सींग की कीमत 63 मिलियन डॉलर से 192 मिलियन डॉलर थी.

लकड़ी का अवैध व्यापार

- ईयू और अमेरिका हर वर्ष करीब 33.5 अरब टन उष्णकटिबंधीय लकड़ी का आयात करता है. अनुमान है कि सभी संदेहास्पद अवैध उष्णकटिबंधीय लकड़ी का 62 से 86 फीसदी कागज, लुग्दी या लकड़ी के चिप्स के रूप में ईयू और अमेरिका जा रहा है.
- वनों की अवैध कटाई का सालाना अनुमानित कारोबार 30 से 100 अरब डॉलर का है. इसे कुल वैश्विक लकड़ी व्यापार का 10 से 30 फीसदी भी कह सकते हैं.
- एक अनुमान के मुताबिक कुछ व्यक्तिगत उष्णकटिबंधीय देशों से आने वाली 50 से 90 फीसदी लकड़ी का अवैध स्रोतों से आने का संदेह है या उन्हें अवैध रूप से काटा जाता है.
- अफ्रीकी देशों और उसके आसदृपास के इलाकों में नागरिक सेना और आतंकवादी समूह जारी हिंसा के दौरान अवैध और अनियमित चारकोल व्यापार के जरिए सालाना 111 मिलियन डॉलर से 289 मिलियन डॉलर की कमाई कर रहा है.
- एक अनुमान के मुताबिक पूर्वी अफ्रीका का एक आतंकवादी समूह चारकोल के अवैध व्यापार से सालाना 38 से 56 अरब डॉलर की कमाई कर रहा है.

सिफारिशें

- पर्यावरण कानून और नियमों पर प्रयासों में समन्वय, गरीबी उन्मूलन और विकास का समर्थन करने में मदद करके समन्वित यूनएन और पर्यावरण अपराध के लिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण लागू करना.
- पर्यावरण अपराध के आयामों, पर्यावरण पर पड़ने वाले गंभीर प्रभावों और सतत विकास लक्ष्यों को स्वीकर करते हैं और सूचना साझा करने में मदद करेंगे.
- यूएनईपी को वैश्विक पर्यावरणीय अधिकारी के रूप में सहयोग देना ताकि वह पर्यावरण अपराध से बढ़ रहे गंभीर पर्यावरणीय प्रभावों को संबोधित कर सके और यूएन प्रणाली के प्रासंगित समन्वय तंत्रों को देशों और राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को प्रासंगिक पर्यावरण जानकारी के साथ मदद कर सके.
- उपभोक्ता जागरूकता अभियान और उपयोगकर्ता बाजारों की पहचान कर भ्रष्टाचार से निपटने के लिए संस्थागत, कानूनी और नियामक प्रणाली को मजबूत बनाना और अवैध व्यापार की निगरानी और प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करना.
- अपराधी समुदाय को पर्यावरण अपराध को सतत विकास और राजस्व के लिए गंभीर खतरा समझाने के लिए और अवैध व्यापार को रोकने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक प्रयासों के कार्यान्वयन और प्रवर्तन का समर्थन करना.
- पर्यावरण कानून, अनुपालन और जागरूकता को मजबूत बनाने और प्रवर्तन एजेंसियों और देशों को गैरदृ राज्य सशस्त्र गुटों और आतंकवाद को वित्तपोषण और अवैध व्यापार की भूमिका को कम करने के लिए.

पुरस्कार/सम्मान

49वें ज्ञानपीठ पुरस्कार

49वें ज्ञानपीठ पुरस्कार हेतु 20 जून 2014 को हिन्दी के कवि केदारनाथ सिंह के नाम की घोषणा की गई. वर्ष 2013 के लिए घोषित 49वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा भारतीय ज्ञानपीठ के निदेशक लीलाधर मंडलोई ने की. केदारनाथ सिंह इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले हिन्दी के 10वें रचनाकार हैं. उन्हें पुरस्कार स्वरूप 11 लाख रुपये, प्रशस्ति पत्र, वाग्देवी की प्रतिमा एवं शाल भेंट किये जायेंगें.

केदारनाथ सिंह को अज्ञेय द्वारा संपादित श्तीसरा सप्तकश के एक सशक्त कवि के रूप में ख्याति मिली थी. हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि केदारनाथ सिंह का जन्म वर्ष 1934 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के चकिया गाँव में हुआ. इन्होंने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (वाराणसी) से वर्ष 1956 में हिन्दी में एम.ए. और वर्ष 1964 में पी. एच.डी. की उपाधि प्राप्त की.

केदारनाथ सिंह जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय (दिल्ली) के हिन्दी विभाग में प्राध्यापक एवं अध्यक्ष रहे.

- ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है.
- ज्ञानपीठ पुरस्कार 'भारतीय ज्ञानपीठ न्यास' द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है.
- यह पुरस्कार भारतीय संविधान के आठवीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं में से किसी भाषा के लेखक को प्रदान किया जाता है.
- वर्ष 2011 से पुरस्कार स्वरूप 11 लाख रुपए नकद, शॉल व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है. इसके पहले इस सम्मान के तहत 7 लाख रुपए नकद दिए जाते थे.
- वर्ष 2011 में भारतीय ज्ञानपीठ ने पुरस्कार राशि को 7 से बढ़ाकर 11 लाख रुपए किए जाने का निर्णय लिया था.
- वर्ष 1965 में 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि से प्रारंभ हुए, इस पुरस्कार को वर्ष 2005 में 7 लाख रुपए कर दिया गया.
- प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप को प्रदान किया गया था.
- वर्ष 1982 तक यह पुरस्कार लेखक की एकल कृति के लिए दिया जाता था. लेकिन इसके बाद से यह लेखक के भारतीय साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने लगा.

ज्ञातव्य हो कि केदारनाथ सिंह इस पुरस्कार को हासिल करने वाले हिन्दी के 10वें साहित्यकार हैं. इससे पूर्व हिन्दी साहित्य के जाने माने हस्ताक्षर सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सयायन अज्ञेय, महादेवी वर्मा, नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण, श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को यह पुरस्कार दिया जा चुका है.

लीजन ऑफ ऑनर

फ्रांस ने 25 जून 2014 को शाहरूख खान को सिनेमा में उनके योगदान के लिए लीजन ऑफ ऑनर अधिकारी के तौर पर सम्मानित करने की घोषणा की. यह सम्मान फ्रेंच और विदेशी नागरिकों को फ्रांस द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है.

शाहरूख खान को यह सम्मान 30 जून 2014 को फ्रांस के विदेश मंत्री लौरेट फैबियस के भारत यात्रा के दौरान दिया जाएगा.

अमिताभ बच्चन के बाद शाहरूख खान बॉलिवुड के दूसरे अभिनेता हैं जिन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है. अमिताभ बच्चन को यह सम्मान 2007 में मिला था.

इस सम्मान से सम्मानित किए जाने वाले अन्य विख्यात भारतीय हैं – लता मंगेशकर और सत्यजीत रे.

इससे पहले, फ्रांस की सरकार ने 2007 में शाहरूख खान को फिल्मों में योगदान के लिए ऑफिर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान से नवाजा था.

भारत सरकार ने शाहरूख खान को 2005 में पद्मश्री से सम्मानित किया था.

ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर के बारे में

ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर एक फ्रेंच सम्मान है जिसकी स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने 19 मई 1802 को की थी.

यह फ्रांस का सबसे बड़ा सम्मान है और पांच डिग्री में विभाजित हैदृ शेवेलियर (नाइट), ऑफिसर (ऑफिसर), कमांड्यूर (कमांडर), ग्रैंड ऑफिसर (ग्रांड ऑफिसर) और ग्रांड क्रोइक्स (ग्रांड क्रॉस).

पुस्तकें

- ब्लड फ्यूड

एडवर्ड क्लेन द्वारा लिखित पुस्तक ब्लड फ्यूड

एडवर्ड क्लेन द्वारा लिखित पुस्तक ब्लड फ्यूड – ओबामा बनाम क्लिंटन जारी की गई. पुस्तक को रेग्नेरी पब्लिशिंग हाउस ने प्रकाशित किया.

पदत्याग/पदमुक्त

पदत्याग/पदमुक्त

- *अली लारायेद*
- *एनरिको लेट्टा*
- *डीके जोशी*
- *रिशांक कीशिंग*
- *एन किरण कुमार रेड्डी*
- *पूर्व न्यायाधीश न्यामूर्ति एके गांगुली का पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा*
- *अरविंद केजरीवाल*
- *विजय बहुगुणा*

सैम पित्रोदा

सैम पित्रोदा ने जनसूचना–संरचना एवं नवाचार मामलों के लिए प्रधानमंत्री के सलाहकार एवं *राष्ट्रीय नवाचार परिषद* (National Innovation Council) के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया. सैम पित्रोदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा ई–मेल से जून को भेजा.

- सैम पित्रोदा भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
- वह भारतीय दूरसंचार आयोग (India´s Telecom Commission) के प्रथम एवं संस्थापक अध्यक्ष थे.
- सैम पित्रोदा प्रसार भारती के संस्थागत ढांचे की समीक्षा हेतु विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष थे.
- गुजरात मूल के सत्यनारायण गंगाराम पांचाल उर्फ सैम पित्रोदा बढ़ई समुदाय से हैं. उनके पिता गुजरात से उड़ीसा में बस गए थे.
- सैम पित्रोदा का जन्म ओडीसा में हुआ था.

निर्वाचित/नियुक्त

- चंद्रबाबू नायडू
- ज्यां क्लाड जंकर

चंद्रबाबू नायडू

आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ईएसएल नरसिम्हन ने तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के नेता चंद्रबाबू नायडू को 5 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया. चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के विभाजन (तेलंगाना) के बाद यहां के मुख्यमंत्री नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति हैं. शपथ ग्रहण 8 जून को होगा. *ज्ञातव्य हो कि आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव 2014 का परिणाम 17 मई 2014 को घोषित हुआ. चन्द्र बाबू नायडू के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश के नवगठित 175 सदस्यीय विधानसभा में तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) को 102 सीटें प्राप्त हुई तथा तेदेपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी.*

चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है. वे वर्ष 1995 से वर्ष 2004 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं. उनके नाम आंध्र प्रदेश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का कीर्तिमान भी है.

ज्यां क्लाड जंकर

ज्यां क्लाड जंकर 26 जून 2014 को यूरोपीय आयोग के नए राष्ट्रपति चुने गए. उन्हें ब्रिटेन और हंगरी को छोड़कर यूरोपीय आयोग के सभी सदस्य देशों का समर्थन प्राप्त मिला. वे नवंबर 2014 से अपना पदभार संभालेंगे. वे जोस मैनुअल बारोसो का स्थान लेंगें.

ज्यां जंकर लक्समबर्ग के भूतपूर्व प्रधानमंत्री और ईयू के काफी करीब हैं. ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने जंकर के नामांकन को यूरोप के लिए एक बुरा दिन बताया है.

ज्यां क्लाड जंकर एक राजनीतिज्ञ हैं. वे यूरोपीय संघ के किसी भी देश के सरकार के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रमुख थे. विश्व में लोकतांत्रिक तौर पर चुने गए नेताओं में सबसे लंबे समय तक अपनी सेवा देने वाले नेता भी रहे हैं. साल 1995 से 2013 तक लक्जमबर्ग के प्रधानमंत्री थे.

निधन/मृत्यु

- एरियल शेरॉन
- सुचित्रा सेन

एरियल शेरॉन

इजराइल के मिस्टर सिक्योरिटी कहे जाने वाले एरियल शेरॉन नहीं रहे। आठ साल तक कोमा में रहने के बाद उन्होंने शनिवार को अंतिम सांस ली। इजरायल जहां उन्हें हमेशा बुलडोजर के तौर पर याद रखेगा, वहीं फिलीस्तीन श्सबसे बड़े कसाईश को कभी नहीं भूल पाएगा। विवादास्पद, लेकिन दमदार नेता के तौर पर शेरॉन हमेशा याद रखे जाएंगे।

1. जन्म फिलीस्तीन में 1928 में हुआ। 1948–49, 1950 और 1967 के इजरायली युद्धों में हिस्सा लिया। हर मोर्चे पर सामने रहकर नेतृत्व किया।
2. 1973 में पहली बार संसद के लिए चुने गए और 1977 में पहली बार मंत्री बनाए गए। 1982 में लेबनान पर हुए इजराइली हमले के पीछे उन्हीं का दिमाग था।
3. 1990 की शुरुआत में उन्होंने पश्चिमी तट और गाजा पट्टी में बड़े पैमाने पर यहूदी बस्तियां बसाईं। बाद के सालों में शेरॉन ने इन्हीं बस्तियों को हटवाया। देश में ही विरोध हुआ। खुद की पार्टी–लिकुद से अलग हो गए।

सुचित्रा सेन

बांग्ला सिनेमा की महानायिका सुचित्रा सेन का कोलकाता के अस्पताल में आज निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार थीं। देर शाम 82 वर्षीय अदाकारा को सांस लेने में तकलीफ बढ़ गई थी। गुजरे जमाने की अदाकारा को श्वसन तंत्र में संक्रमण को लेकर 23 दिसंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

सुचित्रा का जन्म आज के बांग्लादेश के पाब्ना जिले में 1931 में हुआ था। इन्होंने 1952 में पहली फिल्म शेष कथा में अभिनय किया, लेकिन यह फिल्म रिलीज नहीं हुई। इसके अगले साल इनकी फिल्म ***7 नंबर कैदी*** आई। इसके बाद 1955 में विमल रॉय की बांग्ला फिल्म देवदास में पारो का किरदार निभाया।

बॉलीवुड में भी इन्होंने कई फिल्में कीं। इसमें से फिल्म ***आंधी*** की खासी चर्चा रही। सुचित्रा सेन को 1972 में पद्मश्री सम्मान मिला। 2012 में इन्हें ***पश्चिम बंगाल सरकार के सर्वश्रेष्ठ अवार्ड बंग भूषण*** से सम्मानित किया गया।

खेल/खिलाड़ी

- *35वें राष्ट्रीय खेलों के तिथियों की घोषणा*
- *आईबीएसएफ 6–रेड वर्ल्ड स्नूकर खिताब*

35वें राष्ट्रीय खेलों के तिथियों की घोषणा

भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने 35वें राष्ट्रीय खेलों की तिथियों की घोषणा 26 जून 2014 को तिरूवनंतपुरम में की. पैंतीसवें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 31 जनवरी से 14 फरवरी 2015 के बीच केरल के सात जिलों में 32 अलग–अलग स्थानों पर किया जाएगा.

35वें राष्ट्रीय खेलों में 36 खेल शामिल होंगें. इसमें कुल 11641 प्रतिभागी हिस्सा लेंगें जिसमें से 7744 एथलिट होंगे. सभी प्रतिभागी कुल 365 स्वर्ण पदक और रजत पदक के साथ 477 कांस्य पदक के लिए मुकाबला करेंगें.

यह दूसरी बार है जब केरल राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा. पहली बार केरल ने 1987 में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया था

शुभंकर

35वें राष्ट्रीय खेलों का लोगो और शुभंकर का अनावरण 11 दिसंबर 2009 को ही कर दिया गया था.

- **शुभंकरः *अम्मू, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल***
- **लोगोः *कनिकोनन*** (भारतीय अमलतास) के पैटर्न में डिजाइन किया हुआ. नेट्टिपट्टम (हाथियों का त्योहारी मास्क) के जैसा.
- भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव – राजीव मेहता
- भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष – एन रामचंद्रन
- 35वें राष्ट्रीय खेलों के सद्भावना राजदूत – सचिन तेंडुलकर
- 2011 में 34वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन रांची, झारखंड में किया गया।
- 2007 33वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन असम में किया गया।

उल्लेखनीय है कि पहले राष्ट्रीय खेल 1924 में भारतीय ओलंपिक खेल के नाम से लाहौर में आयोजित किये गये थे. 1940 में भारतीय ओलंपिक खेल राष्ट्रीय खेल में बदल गए. स्वतंत्रता के बाद पहले राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 1948 में लखनऊ में हुआ था.

आईबीएसएफ 6–रेड वर्ल्ड स्नूकर खिताब

भारतीय खिलाड़ी पंकज ऑडवाणी ने 29 जून 2014 को अपना पहला आईबीएसएफ 6–रेड वर्ल्ड स्नूकर खिताब मिस्र के शर्म अल शेख में जीता. उन्होंने फाइनल में पोलैंड के केसपर पिलपिक को हराया, जो एक घंटो तक चला.

इस जीत ने ऑडवाणी को स्नूकर और बिलियर्ड के शॉर्ट और लांग दोनो प्रारुपों का खिताब जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बनने में मदद की. यह ऑडवाणी का पहला आईबीएसएफ 6– रेड वर्ल्ड और कुल मिलाकर नौवां खिताब था. यह खिताब जीतने के बाद ऑडवाणी इस वर्ग में सबसे ज्यादा खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं.

- पंकज ने अपना पहला खिताब 18 वर्ष की आयु में जीता था और स्नूकर और बिलियर्डस दोनों वर्गों में खिताब जीतने वाले पहले एशियाई हैं.
- पंकज राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान से सम्मानित होने वाले सबसे युवा भारतीयों में से हैं.
- पंकज को अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है.

आलेख

4 जी सर्विस

2 जी और 3 जी के बाद अब देश में जल्द ही 4 जी सर्विस शुरू होने जा रही है। कुछ टेलीकॉम कंपनियों ने इसकी शुरुआत प्रायोगिक तौर पर कर दी है। बाकी कंपनियां 4 जी सर्विस को शुरू करने की तैयारियों में जुटी हैं। उम्मीद की जा रही है कि भारत में जिस तरह से 2 जी और 3 जी को लोगों का समर्थन मिला है, वैसा ही समर्थन 4 जी को भी मिलेगा।

रिलायंस जिओ

रिलायंस जिओ इंफोकॉम बहुप्रतीक्षित 4जी सर्विस की शुरुआत इंदौर, कोयंबटूर जैसे छोटे शहरों से करेगी। इंडस्ट्री सूत्रों और विश्ष्लेषकों का कहना है कि छोटे शहरों से शुरुआत करने के बाद रिलायंस जिओ मेट्रो शहरों की ओर रुख करेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज की टेलीकॉम यूनिट रिलायंस जिओ 4जी सर्विस शुरू करने से पहले प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर और अफोर्डेबल हैंडसेट और डिवाइस को बाजार में लाने पर उग्रता से काम कर रही है।

जिओ ने सभी 22 टेलीकॉम सर्किल में मुख्यालय बनाने की भी योजना बनाई है। इन प्रत्येक मुख्यालय पर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी। इससे पहले खबर आई थी कि जिओ 500 टेक्नीशियन की भर्ती करेगी।

वीडियोकॉन टेलीकॉम

वीडियोकॉन टेलीकॉम ने अपने 7 में से छह सर्किल में 4जी सर्विस लांच करने के लिए चीन की उपकरण निर्माता कंपनी हुवेई टेक्नोलॉजी के साथ गठजोड़ किया है। वीडियोकॉन टेलीकॉम के डायरेक्टर व सीईओ अरविंद बंसल के मुताबिक वीडियोकॉन भारत में छह टेलीकॉम सर्किल में हुवेई के एलटीई–रेडी पैकेट कोर नेटवर्क की मदद से 4जी सर्विस लांच करेगी। यह नेटवर्क बहुत सस्ती दरों पर उपभोक्ताओं को वृहद डाटा कवरेज उपलब्ध कराएगा।

वोडाफोन

वोडाफोन इंडिया ने कुछ सर्किल में 1800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम हासिल किया है। इसके जरिये कंपनी एलटीई टेक्नोलॉजी के जरिये 4 जी सर्विस लांच करेगी। वोडाफोन अगले साल से 4 जी के लिए नेटवर्क स्थापित करने के लिए काम शुरू करेगी। फिलहाल कंपनी 3 जी सर्विस के सहारे ही काम चलाएगी। नेटवर्क पूरा होने के बाद ही वोडाफोन 4 जी सर्विस शुरू करेगी।

भारती एयरटेल

भारती एयरटेल ने हाल ही में पंजाब में

मोहाली के बाद लुधियाना में अपनी 4 जी सर्विस लांच की है। कंपनी अपने पोस्टपेड ग्राहकों को यह सुविधा 100 रुपए के शुरुआती पैकेज पर उपलब्ध करवा रही है। एयरटेल ने इससे पहले बैंगलुरू, कोलकाता, पुणे, चंडीगढ़ और पंचकुला में भी 4 जी सर्विस जल्द शुरू करने जा रही है। एयरटेल ने डोंगल, वाय–फाय सीपीई और मोबाइल फोन पर एक साथ 4 जी सर्विस की शुरुआत की है।

कैसे और क्या होती है ई–वोटिंग

इन्वेस्टर शेयरहोल्डर के तौर पर शेयरहोल्डर मीटिंग के दौरान वोट देकर कंपनी के अहम फैसलों में शामिल हो सकता है, लेकिन मीटिंग में शामिल होना या कंपनी को पोस्टल बैलट भेजना प्रॉक्सी वोटिंग जैसा है और ऐसा करना मुश्किल लग सकता है। शेयरहोल्डर्स अब ई–वोटिंग फैसिलिटी के जरिए डिसिजन मेकिंग प्रॉसेस में शामिल हो सकते हैं। एनएसडीएल और सीडीएसएल यह फैसिलिटी मुहैया करा रही हैं।

कौन कर सकता है ई–वोटिंग?

रिजॉल्यूशन पास करने के लिए नोटिस भेजे जाने की तारीख को जिन शेयरहोल्डर्स का नाम कंपनी के मेंबर्स के रजिस्टर में होगा, वे ई–वोटिंग के जरिए वोट करने के हकदार होंगे। ई–वोटिंग के लिए जरूरी नहीं है कि शेयरहोल्डर्स की होल्डिंग डीमैट फॉर्मेट में हो। शेयर, फिजिकल या डीमैट, किसी भी फॉर्मेट में हों, उनके होल्डर्स को वोटिंग की इजाजत होगी, हालांकि इस फैसिलिटी को यूज करना जरूरी नहीं है।

इन्वेस्टर्स को पोस्टल बैलेट या ई–वोटिंग फैसिलिटी के जरिए रिजॉल्यूशन पास करने के बारे में जानकारी ईमेल के जरिए या लेटर से भेजी जाती है। इस सूचना में ई–वोटिंग के लिए मीटिंग का नोटिस, पास होने वाले प्रस्तावित रिजॉल्यूशन, पोस्टल बैलट फॉर्म, ई–वोटिंग इवेंट नंबर और यूजर आईडी के साथ पासवर्ड भेजा जाता है।

रजिस्ट्रेशन और वोटिंग

इन्वेस्टर्स एनएसडीएल या सीडीएसएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लॉग–इन करने पर उस रिजॉल्यूशन वाला वेब पेज पर दिखता है, जिसके लिए वोटिंग होनी है। इन्वेस्टर को शेयरों की संख्या बताने के बाद यह सिलेक्ट करना होता है कि क्या वह रिजॉल्यूशन के सपोर्ट में वोट देना चाहता है कि उसके खिलाफ।

टाइम पीरियड

नोटिस में ई–वोटिंग के टाइम पीरियड के बारे में बता दिया जाता है। जितना वक्त पोस्टल

बैलट के जरिए वोट डालने के दिया जाता है, उतना ही वक्त ई–वोटिंग के लिए भी फिक्स रहता है।

इन्वेस्टर्स वोट करने के लिए चाहें तो ई–वोटिंग फैसिलिटी यूज कर सकते हैं या पोस्टल बैलेट भेज सकते हैं, लेकिन एक साथ दोनों फैसिलिटी यूज नहीं की जा सकती।

ई–वोटिंग करने वाले इन्वेस्टर्स को इस बात का फायदा मिलता है कि वे अपना वोट अंतिम तारीख तक दे सकते हैं। इससे उनके वोट के इनवैलिड करार दिए जाने का खतरा नहीं होता है।

क्या है अर्निंग यील्ड?

एंटरप्राइज वैल्यू, रिटर्न ऑन इक्विटी, प्राइस टु सेल्स और प्राइस टु इक्विटी जैसे सभी इक्विटी वैल्यूएशन रेश्यो का यूज शेयरों के तुलनात्मक अध्ययन में किया जा सकता है। इन रेश्यो के जरिए एक ही इंडस्ट्री के कई शेयरों में अंडरवैल्यूड शेयर की पहचान की जा सकती है।

अगर कोई बॉन्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट, ट्रेजरी और जी–सेक जैसे दूसरे असेट क्लास से शेयर के परफॉर्मेंस की तुलना करना चाहे तो क्या होगा? जिस पैमाने से इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स के परफॉर्मेंस को एक दूसरे की तुलना में तोला जा सकता है, वह है यील्ड। डेट इंस्ट्रूमेंट की यील्ड को उसके पीरियोडिक कैश फ्लो, मार्केट प्राइस और टाइम टु मैच्योरिटी से कैलक्युलेट किया जाता है।

शेयर की यील्ड कैसे पता की जाती है?

किसी शेयर की यील्ड को अर्निंग यील्ड कहते हैं। यह रेश्यो प्राइस टु अर्निंग (P/E) रेशियो से हासिल किया जाता है। यह कुछ और नहीं P/E रेश्यो का उलटा है। उदाहरण के लिए, 20 P/E रेश्यो वाले शेयर की अर्निंग यील्ड 5 फीसदी होगी यानी 1/20। स्टॉक की यील्ड कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका यह है कि ईपीएस (पिछले 12 महीने की नेट अर्निंग से हासिल ईपीएस) में करेंट मार्केट प्राइस से भाग दिया जाए। अर्निंग यील्ड से पता चलता है कि इन्वेस्टर के हर एक रुपये पर कंपनी के मुनाफे में उसका कितने पैसे का हक है। ऊपर के उदाहरण में हर 100 रुपये के इन्वेस्टमेंट पर इन्वेस्टर को कंपनी के नेट प्रॉफिट में 5 रुपये का दावा होगा।

यह इंपॉर्टेंट क्यों है?

गवर्नमेंट सिक्यॉरिटी और अर्निंग यील्ड की ऐनालिसिस से इक्विटी रिस्क प्रीमियम का पता चलता है। इक्विटी रिस्क प्रीमियम वह ऐडिशनल रिटर्न है, जो स्टॉक मार्केट को उससे जुड़े रिस्क उठाने के लिए रिस्क फ्री रिटर्न के अलावा ऑफर करना चाहिए। जी–सेक की यील्ड रिस्क–फ्री मानी जाती है, क्योंकि इसे सरकार की सॉवरेन गारंटी मिली होती है। अर्निंग यील्ड और जी सेक यील्ड के बीच का फर्क यह तय करने में अहम रोल अदा करता है कि क्या कोई शेयर अंडरवैल्यूड या ओवरवैल्यूड है। फर्क बढ़ने पर शेयर का अंडरवैल्यूएशन बढ़ता है क्योंकि वह पर्याप्त रिस्क प्रीमियम जेनरेट करने लगता है। दूसरी तरफ, फर्क घटना ओवरवैल्यूएशन का संकेत है। इस बात को एक उदाहरण से समझा जा सकता है। एक साल का औसत जीसेक बॉन्ड यील्ड 8.2 फीसदी है। इन्वेस्टर बिना कोई कैपिटल रिस्क उठाए इतना कमा सकता है तो उसके मुकाबले शेयर तभी अट्रैक्टिव होगा, जब उसकी यील्ड इससे ज्यादा हो।

करेंट एकाउंट डेफिसिट की फंडिंग

किसी देश के करंट अकाउंट डेफिसिट (सीएडी) से पता चलता है कि उसने गुड्स, सर्विस और ट्रांसफर्स के एक्सपोर्ट के मुकाबले कितना ज्यादा इंपोर्ट किया है। यह जरूरी नहीं है कि करंट अकाउंट डेफिसिट देश के लिए नुकसानदेह ही होगा। विकासशील देशों में लोकल प्रोडक्टिविटी और फ्यूचर में एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए शॉर्ट टर्म में करंट अकाउंट डेफिसिट हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में करंट अकाउंट डेफिसिटी इकॉनमी का दम निकाल सकती है।

सीएडी की फंडिंग कैसे की जा सकती है?

करंट अकाउंट डेफिसिट की फंडिंग कई तरह के कैपिटल फंड इनफ्लो से की जाती है। इसमें पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल कमर्शल बॉरोइंग यानी ईसीबी, फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स (एफडीआई) और एनआरआई डिपॉजिट शामिल हो सकते हैं। सीएडी की फाइनैंसिंग के पर्याप्त संसाधन नहीं होने से लोकल करेंसी की वैल्यू कम होती है।

सीएडी की फंडिंग का आदर्श तरीका क्या है?

इसका सबसे अच्छा तरीका फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जैसा नॉन–डेट क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म इनफ्लो है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट (कभी–कभार हॉट मनी कहलाने वाले) जैसे उतार–चढ़ाव वाले फंड इनफ्लो से एक्सटर्नल सेक्टर की बैलेंसशीट गड़बड़ा सकती है।

इंडिया का एक्सपीरियंस कैसा रहा है?

हाल के दिनों में इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी के 4 फीसदी तक पहुंच गया था, लेकिन पर्याप्त कैपिटल इनफ्लो नहीं रहने से डॉलर के मुकाबले लोकल करंसी रुपए में कमजोरी आई। इसके चलते डॉलर की डिमांड पूरी करने के लिए रिजर्व बैंक को मजबूरन अपने स्टॉक से डॉलर बेचना पड़ा।

रेगुलेटर और पॉलिसीमेकर्स परेशान क्यों हैं?

करंट अकाउंट डेफिसिट को घटाने के उपाय बहुत कम रह गए हैं, क्योंकि हर हाल में इंपोर्ट होने वाली चीजों की कीमत बढ़ रही है। इंडिया की इकनॉमिक हालत को देखते हुए इसका सीएडी 2.5 फीसदी होना चाहिए। सरकार ने एक्सपोर्ट बढ़ाने के उपाय किए हैं। इसका असर भी दिखने लगा है। जुलाई–अगस्त में एक्सपोर्ट ग्रोथ अच्छी रही है।